भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1121

जिसका उत्तर दिनांक 29.07.2021 को दिया जाना है

इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा डाटा माइनिंग

1121 डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) ने डाटा वेयरहाउसिंग और डाटा माइनिंग के संबंध में कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या ईसीआईएल ने ई-शासन के संबंध में क्षमता निर्माण के लिए अन्य सरकारी संगठनों/विभागों/एजेंसियों के साथ सहयोग किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह) :

(क) जी, हां ।

(ख) डाटा वेयरहाउसिंग में ईसीआईएल की पहल का क्रियान्वयन राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और दिल्ली पुलिस के एकीकृत सुरक्षा प्रणालियों में किया गया है, जहाँ पर डाटा वेयरहाउस कई विभिन्न प्रकार के संवेदियों से प्रग्रहित इलेक्ट्रानिक डाटा के बड़े परिमाण को एकीकृत कर निर्मित किया जाता है, जिसे सुरक्षा प्रचालनों में उपयोगी अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराने के लिए पुनः प्राप्त कर विश्लेषण किया जा सकता है । डाटा का उपयोग घटना प्रबंधन, घटनोपरांत विश्लेषण और फोरेन्सिक साक्ष्य के लिए सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किया जाता है ।

डाटा माइनिंग में पहलों का क्रियान्वयन अंतर्गृह-निर्मित सुरक्षित निर्माण प्रक्रिया में किया गया है, जिसका उपयोग यंत्र अधिगम एवं गहन अधिगम एल्गोरिथमों का प्रयोग करके अनुरेखनीयता, संरचना उत्पादों का विश्लेषण, भविष्यसूचक एवं विफलता विश्लेषण हेतु सामरिक इलेक्ट्रानिक उपस्करों के उत्पादन के लिए किया जाता है । भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता के कृत्रिम बुद्धिमता केन्द्र के सहयोग से स्वचालित दूरदर्शिता आधारित निरीक्षण प्रणाली हेतु गहन अधिगम तकनीकों के विकास एवं इस्तेमाल के लिए भी पहल की गई है ।

(ग) जी, हां । ईसीआईएल ने ई-शासन के अग्रानुक्रम में क्षमता निर्माण हेतु भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल) और इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज (आईटीआई) के साथ सहयोग किया है । ये सहयोग गृह मंत्रालय (एमएचए), ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) और मत्सय पालन विभाग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर), सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), समुद्री मात्स्यिकी पहचान पत्र (एमएफआईडी) परियोजनाओं में किया गया है ।

इस सहयोग ने ई-शासन परियोजनाओं के लिए कुशल मानवशक्ति विकास, ई-शासन से संबंधित परियोजना गतिविधियों को संभालने के लिए इन-हाउस आईटी-अवसंरचना के उन्नयन, उच्च-स्तरीय स्वदेशी अनुप्रयोगात्मक सॉफ्ट्वेयर एवं डाटाबेस संरचना को विकसित करने योग्य मानवशक्ति के सृजन और स्मार्ट कार्ड प्रिंटिंग एवं निजीकरण की इन-हाउस विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना को सुगम बनाया ।

* * * * *